No.14014/19/2000-Estt(D)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.
(Department of Personnel and Training)

New Delhi-110001
November 24, 2000

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Appointment on compassionate ground - Termination of service.

The undersigned is directed to refer to the Department of Personnel and Training (DoP&T) Office Memorandum No.14014/16/99-Estt(D) dated December 20, 1999 (copy enclosed) which provides that in the case of compassionate appointment, the offer of appointment should contain a specific condition to the effect that a person appointed on compassionate grounds under the scheme should give an undertaking in writing that he/she will maintain properly the other family members who were dependent on the Government servant/member of the Armed Forces in question and in case it is proved subsequently (at any time) that the family members are being neglected or are not being maintained properly by him/her, his/her appointment may be terminated forthwith. The procedure to be followed in general for such termination, particularly the question whether the procedure prescribed in the Disciplinary Rules/Temporary Service Rules should be followed or not has been examined in consultation with the Ministry of Law (Department of Legal Affairs). It has been decided that such compassionate appointments can be terminated on the ground of non-compliance of any condition stated in the offer of appointment after providing an opportunity to the compassionate appointee by way of issue of show cause notice asking him/her to explain why his/her services should not be terminated for non-compliance of the condition(s) in the offer of appointment and it is not necessary to follow the procedure prescribed in the Disciplinary Rules/Temporary Service Rules for this purpose.

2. In order to check its misuse, it has also been decided that this power of termination of services for non-compliance of the condition(s) in the offer of compassionate appointment should vest only with the Secretary in the concerned administrative Ministry/Department not only in respect of persons working in the Ministry/Department proper but also in respect of Attached/Sub-ordinate offices under that Ministry/Department.

3. The above decisions may be brought to the notice of all concerned for information, guidance and necessary action.

(K.K. JHA)
DIRECTOR(Establishment)

To

All Ministries/Departments of the Government of India

Copy to:-

1. The Comptroller and Auditor General of India, New Delhi.
2. The Secretary, Union Public Service Commission, New Delhi (**20 copies**)
3. The Rajya Sabha Secretariat, New Delhi.
4. The Lok Sabha Secretariat, New Delhi.
5. All State Governments/Union Territory Administrations.
6. All attached/subordinate offices under the DoP&T/Ministry of Home Affairs.
7. National Commission for SCs/STs, New Delhi.
8. The Secretary, Staff Side, National Council, New Delhi.
9. The Registrar General, The Supreme Court of India, New Delhi.
10. The Ministry of Railways (Railway Board) with reference to their Office Memorandum No.E(NG)II/99/RC-1/Genl/19 dated 19.9.2000.
11. National Commission for OBCs, New Delhi.
12. All Officers/Sections of DoP&T.
13. Facilitation Centre, DoP&T (**20 copies**).
14. NIC (DoP&T Branch) for placing this O.M. on the website of DoP&T.
15. Establishment (D) Section (**500 copies**).

संख्या 14014/19/2000-स्थापना(घ)
भारत-सरकार
कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक नवम्बर 24 , 2000

कार्यालय-ज्ञापन

विषय:-अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति - सेवा समाप्ति के संबंध में ।

अधोहस्ताक्षरी को कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग के दिनांक दिसम्बर 20, 1999 के कार्यालय-ज्ञापन संख्या 14014/16/99-स्था.(घ) (प्रति संलग्न) का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि अनुकम्पा के आधार पर की जाने वाली नियुक्ति के मामले में, नियुक्ति प्रस्ताव में एक स्पष्ट शर्त रखी जाए कि उपर्युक्त योजना के अंतर्गत अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति, लिखित रूप में यह वचन दे कि वह दिवंगत सरकारी कर्मचारी/सशस्त्र सेनाओं के सदस्य के परिवार के अन्य आश्रित सदस्यों का उपयुक्त ढंग से भरण-पोषण करेगा/करेगी और यदि बाद में किसी भी समय यह सिद्ध हो जाता है कि परिवार के सदस्यों की संबंधित सरकारी कर्मचारी/सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों द्वारा उपेक्षा की जा रही है अथवा उचित रूप से भरण-पोषण नहीं किया जा रहा है तो उसकी नियुक्ति तुरंत समाप्त की जा सकती है । सामान्यतः ऐसी सेवा-समाप्ति के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, विशेष तौर पर इस प्रश्न कि क्या अनुशासनिक नियमावली/अस्थायी सेवा नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाए या नहीं, की विधि मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) के परामर्श से जांच की गई है । यह निर्णय किया गया है कि अनुकम्पा के आधार पर प्रदान की गई ऐसी नियुक्ति, नियुक्ति प्रस्ताव में उल्लिखित किसी शर्त का अनुपालन न किए जाने पर, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति किए गए व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी करके उसे यह बताने/स्पष्ट करने का अवसर देते हुए कि नियुक्ति प्रस्ताव में दी गई शर्तों के अनुपालन न करने के मद्देनज़र, उसकी सेवा क्यों न समाप्त कर दी जाए, समाप्त की जा सकती है और इस उद्देश्य हेतु अनुशासनिक नियमावली/अस्थायी सेवा नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन आवश्यक नहीं है ।

2. अनुकम्पा के आधार पर की गई नियुक्ति का दुरूपयोग रोकने की दृष्टि से यह निर्णय किया गया है कि अनुकम्पा के आधार पर दी जाने वाली नियुक्ति संबंधी नियुक्ति-प्रस्ताव में रखी गई शर्तों का उल्लंघन होने पर सेवा समाप्त करने का अधिकार न केवल संबंधित मंत्रालय/विभाग में कार्यरत व्यक्ति के मामले में संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव को होगा बल्कि उस मंत्रालय/विभाग के अंतर्गत आने वाले संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के मामलों में भी उनके उसी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव का होगा ।

3. उपर्युक्त निर्णय सूचना, मार्गदर्शन और आवश्यक कार्रवाई हेतु सभी संबंधित पक्षों के ध्यान में ला दिए जाएं ।

(के.के. झा)
निदेशक (स्थापना)

सेवा में,

भारत-सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग । उपरोक्त /